

The Hindu- 30- October-2022

Rajasthan checking groundwater viability for potable water projects

The Hindu Bureau

JAIPUR

The “source finding committees” in different geographical regions of Rajasthan are being activated to ascertain the sustainability of groundwater, an official said on Saturday.

Accompanied with the quality control, this will be a major step for strengthening drinking water projects in the desert State, which faces a decline in the groundwater table.

Though the good monsoon rain this year helped in improving the drinking water supply to some extent, some of the major projects are yet to be completed. The study of water source sustainability is expected to speed up the projects which have already been sanctioned and

The water source study is expected to speed up the projects which have already been sanctioned

pave the way for new groundwater-based projects.

Subodh Agarwal, Additional Chief Secretary, Public Health Engineering, said here that the quality of work in the drinking water projects would also be ensured by activating the quality control wing. The field engineers will visit the sites to check the progress of project works and take steps to prevent delay. Mr. Agarwal said 29.9 lakh individual tap connections had been released under the Jal Jeevan Mission which envisages supply of safe water to all by 2024.

Navbharat Times- 30- October-2022

आखिर क्यों यमुना में आता है झाग?

■ विस, नई दिल्ली : छठ पर प्रकृति और सूर्य की पूजा की जाती है। कैलाशपुरी छठ पूजा समिति की प्रतिमा देवी के मुलाविक, 'नदियां प्रकृति का रूप हैं। इसलिए यमुना पूजनीय है और इसी वजह से छठ पर उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है।' यमुना में प्रदूषण की बात जितनी छठ पर होती है उतना पूरे साल नहीं। आखिर कहां से आ जाता है अक्टूबर और नवंबर में यह झाग और क्या है इसकी वजह।

यमुना जिये अभियान के मनोज मिश्रा के अनुसार इस झाग की वजह यमुना में नालों व सीवरों के पानी के साथ आ रहा साबुन व डिटरजेंट है। यमुना में अब भी शहर के कई हिस्सों का सीवर का पानी डाला जा रहा है। मॉनसून के बाद जब यमुना का जलस्तर कम होने लगता है तो प्रदूषक कण एक परत बना लेते हैं। खासतौर पर फास्फेट की मात्रा इस झाग की परत के लिए जिम्मेदार है। सीपीसीसी व डीपीसीसी ने भी यमुना में झाग की वजह सफेकट और फास्फेट को माना है।

कहां कितनी है फास्फेट और सफेकट की मात्रा : डीपीसीसी ने दो साल पहले आई एक रिपोर्ट के अनुसार यमुना में सबसे अधिक सफेकट और फास्फेट खजूरी पलटून में पाया गया था। यहां इसकी मात्रा 13.42 एमजी प्रति लीटर रही थी। वहीं ओखला बैराज में इसका स्तर 12.26 एमजी प्रति लीटर, निजामुद्दीन ब्रिज में 11 एमजी प्रति लीटर, पल्ला में इसका स्तर 9.78 एमजी प्रति लीटर रहा था।

नालों में भी मिली इनकी मात्रा : यमुना में गिरने वाले नालों में सबसे अधिक फास्फेट का स्तर (74.5 एमजी प्रति लीटर) नजफगढ़ नाले में मिला। इसके बाद आईएसबीटी नाले में 65.5 एमजी प्रति लीटर, बारापुर नाले में 57.2 एमजी प्रति लीटर और इंद्रपुरी नाले में



यहां दिखता है झाग

छठ के दौरान जब ओखला बैराज के गेट खोले जाते हैं तो पानी काफी उंचाई से यमुना में गिरता है। इसी वजह से झाग की परत बन जाती है। सीपीसीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, झाग की यह परत ओखला बैराज और आईटीओ पर दिखती है। हालांकि एक्सपर्ट के अनुसार नदी में कई जगह पर फास्फेट की मात्रा अधिक हो सकती है, लेकिन अन्य जगहों पर झाग न दिखने की वजह यह है कि वहां पर पानी उंचाई से नदी में नहीं गिरता।

इसका स्तर 54.2 एमजी प्रति लीटर मापा गया।

रोकने के लिए उठाया था कदम : फास्फेट और सफेकट को नदी में जाने से रोकने के लिए जून 2021 में डीपीसीसी ने राजधानी में सिर्फ बीआईएस स्टैंडर्ड के साबुन और डिटरजेंट की बिक्री, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को ही इजाजत दी थी, लेकिन सब स्टैंडर्ड साबुन और डिटरजेंट का इस्तेमाल करने वालों पर क्या कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। अब भी सब स्टैंडर्ड साबुन व डिटरजेंट का प्रयोग आम है।

डीजेबी ने यूपी पर मद्दा दोष : डीजेबी के एक अधिकारी का कहना है कि झाग मुख्य रूप से ओखला बैराज पर ही देखने को मिलता है। वहां यह समस्या यूपी की वजह से है।

यमुना अब तक मैली क्यों, NGT में प्राधिकरणों को देना होगा जवाब

4 नवंबर को दिल्ली, यूपी और हरियाणा की सरकारें होंगी पेश

Prachi.Yadav@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली :** यमुना को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए दशकों से जारी कवायद के बावजूद वह मैली क्यों है, इसका जवाब 4 नवंबर को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में देना है, जिसने एक बार फिर इस मामले में दखल दिया है।

यमुना की दुर्दशा देख सुप्रीम कोर्ट ने 23 वर्षों तक मामले की निगरानी की। एनजीटी जब अस्तित्व में आया तो उसने 13 जनवरी 2015 को एक प्रोजेक्ट तैयार किया- 'मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार परियोजना-2017'। एनजीटी ने 25 जुलाई 2018 को यमुना मॉनिटरिंग कमिटी बनाई, जिसने 16 पॉइंट एक्शन प्लान एनजीटी के सामने रखा। कमिटी ने 2020 में

ग्रीन ट्रिब्यूनल के सवाल...

- प्राधिकारी बताएं, क्यों आज भी तीन 'O' जोन का काम प्लानिंग स्टेज पर ही लटका है?
- यमुना के पानी को दूषित करने वाले नालों को उसमें गिरने से क्यों रोका नहीं जा रहा?
- क्यों नालों के आउटलेट पर एसटीपी लगाने की डेडलाइन बार-बार मिस हो रही है?

अपनी पांचवीं रिपोर्ट पेश की तो अथॉरिटीज की 'कामचोरी' की कलई खुल गई।

चार 'O' जोन में से सिर्फ एक पर हुआ काम: प्रस्तावित परियोजना के पहले फेज में दिल्ली में यमुना के फ्लडप्लेन को अतिक्रमण

मुक्त कराकर उसका सौंदर्योत्थान किया जाना था। इसके लिए उसे चार 'O' जोन में बांट दिया गया। इसका पहला पार्ट लोहे के पुल से गीता कॉलोनी घाट तक था, जिसका काम लगभग पूरा होने का दावा किया गया। दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी के अधिकारी के अनुसार, बाकी 3 जोन का काम अभी प्लानिंग स्टेज पर है। इसके अंतर्गत गीता कॉलोनी से आईटीओ, आईटीओ से निजामुद्दीन और निजामुद्दीन से कालिंदी कुंज तक के जोन शामिल हैं।

एसटीपी की डेडलाइन बार-बार बढ़ रही: यमुना के दूषित होने की प्रमुख वजह उसमें गिरने वाले नाले हैं। इन नालों को यमुना में गिरने से रोकने के लिए उनके आउटलेट पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे, लेकिन सात साल बाद भी यह काम अधर में है।